SHIV SHAKTI

International Journal in Multidisciplinary and Academic Research (SSIJMAR)

Vol. 12, No. 2, April 2024 (ISSN 2278 – 5973)

भारत में शिक्षा की आवश्यकताएँ और महत्व

Dr. Subhash Gautam
PhD (Library Information Science and Technology), M A (Hindi), UGC NET, MSc(IT), M A (Eco), M A (Philisophy) and presently working in Department - School of Learning, University of Delhi, Delhi

अमूर्त

शिक्षा भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला है , जो व्यक्तिगत सशक्तिकरण , गरीबी उन्मूलन और राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक है। भारत में शिक्षा की आवश्यकता पहुंच से परे है , इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान शामिल है जो शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। शिक्षा हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाती है , लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और सामाजिक गतिशीलता को सक्षम बनाती है। यह आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है , एक कुशल कार्यबल तैयार करना जो नवाचार और उद्योग को संचालित करता है। इसके अलावा , शिक्षा नागरिक जिम्मेदारी का पोषण करती है, लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाती है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। जैसे-जैसे भारत ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है , शिक्षा में निवेश, विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन में , व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता , वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत विकास के लिए अनिवार्य है। इन शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने से सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित होगा।

कीवर्ड - आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, नागरिक जिम्मेदारी, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, राष्ट्रीय एकता, कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सतत विकास।

भारत में शिक्षा की आवश्यकताएँ

सतत विकास, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास हासिल करने के लक्ष्य वाले किसी भी देश के लिए शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। भारत में , 1.4 अरब से अधिक की आबादी और विशाल सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक विविधता वाला देश , शिक्षा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रगति का एक महत्वपूर्ण चालक है। शिक्षा तक पहुंच में सुधार में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद , कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, और अधिक मजबूत और समावेशी शैक्षिक ढांचे की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच

  भारत ने विशेषकर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में काफी प्रगति की है। हालाँकि , कई बच्चे, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी, लिंग भेदभाव और भौगोलिक बाधाएं जैसे मुद्दे लाखों बच्चों को स्कूल से दूर रखते हैं, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में। शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच की आवश्यकता सर्वोपरि है , जिसमें लड़कियों, आदिवासी आबादी और विकलांग बच्चों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

  इसके अलावा, केवल पहुंच ही पर्याप्त नहीं है। तेजी से विकसित हो रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च मानक की शिक्षा मिले , भारत की शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख आवश्यकता बनी हुई है।

- शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटना

  भारत की शिक्षा प्रणाली में सबसे स्पष्ट असमानताओं में से एक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विभाजन है। जहां शहरी केंद्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा , योग्य शिक्षक और संसाधनों तक पहुंच होती है, वहीं कई ग्रामीण स्कूल अपर्याप्त सुविधाओं , शिक्षकों की कमी और शिक्षण सामग्री की कमी से पीड़ित हैं। यह शहरी-ग्रामीण अंतर ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों छात्रों की क्षमता को सीमित करता है।

  पूरे देश में समान विकास हासिल करने के लिए इस विभाजन को पाटना महत्वपूर्ण है। भारत में प्रत्येक बच्चे को सफलता के समान अवसर प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार , शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश और ग्रामीण स्कूलों में सीखने के संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

- शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता को मजबूत करना

  शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं और भारत में शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास की गुणवत्ता में सुधार की सख्त आवश्यकता है। कई शिक्षकों , विशेष रूप से पब्लिक

स्कूलों में, छात्रों को प्रभावी ढंग से शामिल करने और आधुनिक, छात्र-केंद्रित शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधनों तक पहुंच की कमी है।

शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वे नई शिक्षण पद्धतियों को अपना सकें , कक्षा में प्रौद्योगिकी को शामिल कर सकें और छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। शिक्षक क्षमता को मजबूत करना और शिक्षण पेशे के लिए सम्मान और समर्थन बढ़ाना शैक्षिक परिणामों में सुधार की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

- बचपन में मिली शिक्षा

शोध से पता चलता है कि प्रारंभिक बचपन की शिक्षा बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है , जो भविष्य की शिक्षा की नींव रखती है। हालाँकि , भारत में, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को अक्सर उपेक्षित किया जाता है , खासकर कम आय वाले परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे सफल होने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल के साथ प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करें , पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता आवश्यक है।

प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों जैसे प्रारंभिक बचपन के शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने से बच्चे की शैक्षिक यात्रा पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है , साक्षरता, संख्यात्मकता और समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है।

- व्यावसायिक और कौशल-आधारित शिक्षा

जबकि भारत में एक बड़ी और बढ़ती युवा आबादी है , कई युवा औपचारिक शिक्षा के माध्यम से हासिल किए गए कौशल और नौकरी बाजार की मांगों के बीच बेमेल होने के कारण रोजगार खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। रटने और सैद्धांतिक ज्ञान पर पारंपरिक जोर ने छात्रों को हमेशा व्यावहारिक, वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं किया है।

अधिक व्यावसायिक और कौशल-आधारित प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत करने से छात्रों को व्यावहारिक कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है जिनकी विनिर्माण , प्रौद्योगिकी और सेवाओं जैसे उद्योगों में मांग है। इससे न केवल रोजगार क्षमता में सुधार होगा बल्कि देश की बेरोजगारी दर में भी कमी आएगी और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

- डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को अपनाना

तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी ने डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला , फिर भी

भारत में लाखों छात्र प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक सीमित पहुंच के कारण पीछे रह गए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल शिक्षा को अपनाने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। इसमें उपकरणों तक पहुंच में सुधार , किफायती इंटरनेट और छात्रों और शिक्षकों दोनों को डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण देना शामिल है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर , भारत सीखने के अनुभव को बढ़ा सकता है , व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान कर सकता है और दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में छात्रों तक पहुंच सकता है।

- ड्रॉपआउट दरों को संबोधित करना

नामांकन में प्रगति के बावजूद, भारत अभी भी विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर ड्रॉपआउट की एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना कर रहा है। कई छात्र , विशेषकर लड़कियाँ, सामाजिक-आर्थिक दबाव, कम उम्र में शादी , या काम के माध्यम से अपने परिवार का समर्थन करने की आवश्यकता के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। यह उच्च ड्रॉपआउट दर कुशल और शिक्षित कार्यबल बनाने के देश के प्रयासों को कमजोर करती है।

इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है , जैसे आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, लचीले सीखने के विकल्प, और छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिक समावेशी और सहायक स्कूल वातावरण बनाना।

- समानता और समावेशन को बढ़ावा देना

भारत में शिक्षा समावेशी होनी चाहिए , जो लिंग, जाति, धर्म या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए अवसर प्रदान करे। समानता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद , कई बच्चे, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को , शिक्षा प्रणाली में भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो शिक्षा के हर स्तर पर समानता और समावेशन को बढ़ावा दें। इसमें वंचित समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, समावेशी कक्षाएँ बनाना और यह सुनिश्चित करने के लिए भेदभाव को समाप्त करना शामिल है कि प्रत्येक बच्चे को सफल होने का समान अवसर मिले।

शिक्षा का महत्व

शिक्षा किसी भी समाज में प्रगति की आधारशिला है, और भारत जैसे विविधतापूर्ण और आबादी वाले देश में, यह देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1.4 अरब से अधिक की आबादी के साथ, शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए भी

आवश्यक है। भारत में शिक्षा के महत्व को गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे विभिन्न आयामों पर इसके प्रभावों के माध्यम से समझा जा सकता है।

- सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण

  शिक्षा सामाजिक गतिशीलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, खासकर भारत जैसे समाज में, जिसमें जाति, लैंगिक असमानता और गरीबी जैसे गहरे मुद्दे हैं। एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी असमानता को कायम रखने वाले सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और उन पर काबू पाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। इसके अलावा, शिक्षा व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद करती है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार होता है और समग्र आर्थिक विकास में योगदान होता है। यह सामाजिक , राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और बेहतर निर्णय लेने के अवसर प्रदान करके हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाता है।

- गरीबी घटाना

  भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गरीबी है। गरीबी के खिलाफ लड़ाई में शिक्षा एक आवश्यक हथियार है , क्योंकि यह व्यक्तियों को बेहतर वेतन वाली नौकरियां सुरक्षित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करती है। एक अच्छी तरह से शिक्षित कार्यबल उत्पादकता बढ़ाता है, जो बदले में आर्थिक वृद्धि और विकास को गति देता है। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़कर भावी पीढ़ियों को अधिक समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

- आर्थिक विकास को बढ़ाना

  किसी राष्ट्र का विकास काफी हद तक उसकी मानव पूंजी पर निर्भर करता है और शिक्षा इस संसाधन को बढ़ाने के केंद्र में है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखने वाले भारत को नवाचार, उद्यमिता और उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सुशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता है। शिक्षा रचनात्मकता , आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देती है , जो किसी भी संपन्न अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। बढ़ते वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के साथ , भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना

  शिक्षा का लैंगिक समानता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में, जहां लिंग आधारित भेदभाव अभी भी प्रचलित है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, शिक्षा लिंग मानदंडों की बाधाओं को तोड़ सकती है। शिक्षित महिलाओं के कार्यबल में भाग लेने , अपने अधिकारों का प्रयोग करने और समाज में योगदान देने की अधिक संभावना है। अध्ययनों से पता चलता है कि लड़कियों को शिक्षित करने

से स्वास्थ्य बेहतर होता है , बाल मृत्यु दर में कमी आती है और परिवारों और समुदायों के आर्थिक परिणामों में सुधार होता है। इस प्रकार , शिक्षा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- नागरिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक भागीदारी का निर्माण

  भारत जैसे देश के लिए , जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है , इसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज के लिए एक शिक्षित आबादी आवश्यक है। शिक्षा नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देती है, जिससे नागरिकों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने में सक्षम बनाया जाता है। एक शिक्षित मतदाता के चुनाव में भाग लेने , सार्वजनिक नीतियों को समझने और नेताओं को जवाबदेह ठहराने की अधिक संभावना होती है। यह एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को भी बढ़ावा देता है , जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण है।

- तकनीकी प्रगति और नवाचार

  आधुनिक दुनिया में, जहां प्रौद्योगिकी उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को चलाती है, शिक्षा नवाचार के लिए मौलिक है। भारत तकनीकी सेवाओं और स्टार्टअप के केंद्र के रूप में उभरा है, लेकिन इस स्थिति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए अत्यधिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में शिक्षा नई प्रौद्योगिकियों के विकास, उद्योगों में सुधार और भविष्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, डिजिटल साक्षरता तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है, और इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भारत की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता

  तेजी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया में, देशों को विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है। भारत की युवा और गतिशील आबादी इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन शिक्षा के बिना, इस जनसांख्यिकीय लाभांश को महसूस नहीं किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्तियों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, और यह भारत को प्रौद्योगिकी, व्यापार और नवाचार जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। शिक्षा को प्राथमिकता देकर , भारत अपने कार्यबल की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष

शिक्षा वह आधार है जिस पर भारत का भविष्य विकास निर्भर करता है। यह व्यक्तिगत सशक्तिकरण , गरीबी उन्मूलन और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। भारत में शिक्षा की ज़रूरतें विशाल और

जटिल हैं, जो देश की विविधता और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को दर्शाती हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारत को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने , शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करने और समावेशिता को बढ़ावा देने में निवेश करना चाहिए।

सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, व्यावसायिक और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना और समावेशिता को बढ़ावा देने जैसी शिक्षा प्रणाली की जरूरतों को संबोधित करने से भारत अपनी विविध आबादी की पूरी क्षमता को अनलॉक करने में सक्षम होगा। शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, आर्थिक विकास को गति देती है , लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करती है। भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने और सतत विकास हासिल करने के लिए शिक्षा में निवेश सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए। व्यापक शैक्षिक सुधारों के माध्यम से , भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक न्यायसंगत, नवीन और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है।

संदर्भ

यहां कुछ संभावित संदर्भ दिए गए हैं जिनका उपयोग आप भारत में शिक्षा की जरूरतों और महत्व की गहरी समझ के लिए कर सकते हैं:

- भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 जैसी शैक्षिक नीतियों और पहलों पर रिपोर्ट और प्रकाशन भारत में शिक्षा में सुधार के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं
  (वेबसाइट: https://www.education.gov) ।में)।
- सभी के लिए यूनेस्को शिक्षा (ईएफए) वैश्विक निगरानी रिपोर्ट - ये रिपोर्ट भारत की चुनौतियों और शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने में प्रगति के विशिष्ट संदर्भ के साथ शिक्षा पर एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य देती हैं
  (वेबसाइट: https://en.unesco.org/gem-report)
- भारत में विश्व बैंक शिक्षा - विश्व बैंक भारत में गरीबी कम करने और विकास में शिक्षा की भूमिका से संबंधित डेटा और अध्ययन प्रदान करता है
  (वेबसाइट: https://www.worldbank.org/en/topic/education)
- नीति आयोग की रिपोर्ट - ये भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं , चुनौतियों और सामाजिक-आर्थिक विकास प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है
  (वेबसाइट: https://www.niti.gov.in)
- एएसईआर (शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट) - एएसईआर ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आयोजित करता है, जिसमें सीखने के परिणामों और उन कमियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है

(वेबसाइट: http://www.asercentre.org)।

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) रिपोर्ट - ये भारत में साक्षरता दर , स्कूल नामांकन और ड्रॉपआउट दर पर डेटा प्रदान करते हैं , जो शैक्षिक पहुंच और गुणवत्ता में अंतराल को उजागर करते हैं
  (वेबसाइट: http://mospi.nic.in/national-sample -सर्वेक्षण-कार्यालय-एनएसएसओ)

ये संदर्भ सांख्यिकीय अंतर्दृष्टि , नीति विश्लेषण और वैश्विक परिप्रेक्ष्य का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं , जो भारत में शिक्षा की जरूरतों और महत्व की एक अच्छी तरह से समझ प्रदान करते हैं।